

“ मुख्य समाचार ”

- राज्य सरकार ने केंद्र से आपदा उपरांत आकलन के तहत 9 हजार 42 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जल्द देने का किया आग्रह।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर राजनैतिक प्रतिशोध के चलते पूर्व सरकार की लोकप्रिय योजनाएं बंद करने का लगाया आरोप।
- संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक— 22 जुलाई से शुरू होगा सत्र।
- प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक कल से ऊना में— पार्टी आगामी योजनाओं व रणनीति पर करेगी विचार।

भेंट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा उपरांत आकलन के तहत 9 हजार 42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जल्द जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और कहा कि यह मामला मंत्रालय के पास लम्बित है और इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के चलते राज्य को इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने एन.डी. आर.एफ. के अंतर्गत लम्बित करीब 60 करोड़ रुपये की राशि भी शीघ्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत मंत्रालय को प्रस्तुत एक सौ 25 करोड़ 84 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना को भी जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में एन.डी.आर.एफ. परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री

इस बीच नई दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की और सड़क परियोजनाओं से जुड़ी मांगों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से रानीताल—कोटला और घुमारवीं—जाहू—सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में पिछले वर्ष बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से एक सौ 72 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि भी जारी करने की मांग की। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी मामलों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ठेकेदारों को सभी परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर राजनैतिक प्रतिशोध के चलते पूर्व सरकार की लोकप्रिय योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन योजना का पैसा भी रोक दिया है और बजट होने के बावजूद भी बेटियों की शादी पर पैसा नहीं दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक जिले में शगुन योजना के सैंकड़ों की संख्या में आवेदन लम्बित पड़े हैं और लोग धनराशि के लिए इधर—उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से पूर्व सरकार की जनहितैशी योजनाओं को बंद करने या रोकने का काम कर रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा कार्यकाल में शगुन योजना की शुरुआत हुई थी जिसके तहत बी.पी.एल. परिवार की बेटियों की शादी में 31 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है और 22 हजार पद इसी वर्ष भरे जा रहे हैं। मंडी जिले में करसोग के श्रीमूल मांहुनाग में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए भ्रष्टाचार के सभी दरवाजों को बंद किया है। इसके परिणामस्वरूप डेढ़ वर्ष के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। राजेश धर्माणी ने करसोग में निर्माणाधीन आई.टी.आई. का कार्य जल्द पूरा करने सहित मांहुनाग में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया।

बजट सत्र

केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारु कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा।

रेलवे

रेलवे सुरक्षा बल-आर.पी.एफ. ने पिछले सात वर्षों के दौरान नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के तहत 84 हजार से अधिक बच्चों को बचाया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, नन्हे फरिश्ते विभिन्न भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित एक मिशन है। मंत्रालय ने कहा कि बचाए गए बच्चे को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है जो बच्चे को माता-पिता को सौंप देती है। बचाए गए बच्चों में घर से भागे हुए, लापता, बेसहारा, अपहृत, मानसिक रूप से विकलांग और सड़क पर रहने वाले बच्चे थे।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। सोलन जिले के सायरी में आज एक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन में उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्चस्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। शांडिल ने कहा कि पुस्तकें और खेल एक युवा को भविष्य का प्रतिभा सम्पन्न नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया।

भाजपा

प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक कल से ऊना में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेशभर से करीब 800 प्रतिनिधियों सहित राष्ट्रीय स्तर के नेता भी भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज ऊना में बैठक की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। पार्टी महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर आगामी योजनाओं व रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि बैठक के सफल आयोजन के लिए पार्टी ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है।

कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को सरकार गिराने के सपने छोड़कर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि उप-चुनाव में हार के बाद विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सरकार गिराने की अगली

तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया है और यह सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

महासंघ

हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी व कानूनगो महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक आज कुल्लू में हुई। महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर करने पर कड़ा विरोध जताया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती है तो महासंघ किसी भी स्तर पर आंदोलन कर सकता है। इस दौरान पटवारी व कानूनगो से जुड़ी कई अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई।

इंटक

हिमाचल प्रदेश इंटक इकाई ने राज्य पथ परिवहन निगम को रोड़वेज का दर्जा देने की मांग की है। इंटक के अध्यक्ष बबलू पंडित ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से निगम का सभी तरह का वित्तीय लेन देन निगम की बजाए विभागीय स्तर पर सरकार के पास होगा और बजट का प्रावधान भी हो सकेगा। इसके अलावा इंटक ने निगम के पीस मील वर्कर्स को अनुबंध पर लाने और चालकों व परिचालकों के बकाया ओवर टाइम व नाइट भत्ते का भुगतान करने सहित सभी वेतन विसंगतियों को दूर करने और करुणामूलक आश्रितों की अनुबंध के स्थान पर नियमित भर्ती किए जाने की मांग की है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- राज्य सरकार ने केंद्र से आपदा उपरांत आकलन के तहत 9 हजार 42 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जल्द देने का किया आग्रह।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर राजनैतिक प्रतिशोध के चलते पूर्व सरकार की लोकप्रिय योजनाएं बंद करने का लगाया आरोप।
- संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक— 22 जुलाई से शुरू होगा सत्र।
- प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक कल से ऊना में— पार्टी आगामी योजनाओं व रणनीति पर करेगी विचार।
